जीजू कुरुविला और अन्य

बनाम

कुंजुजम्मा मोहन और अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 4945-4946)

जुलाई 02, 2013

[जी.एस. सिंघवी और सुधांशु ज्योति न्यायाधिपति]

मोटर वाहन अधिनियम, *1988:* धारा *166* घातक दुर्घटना- मुआवजा - मृतक अमेरिका में कार्यरत है विनिमय दर तय करने की तिथि- व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती - धारित*:* यदि दावेदार भारतीय रुपये *(*आईएनआर*)* में मुआवजे का दावा करने वाली याचिका दायर करता है, तो दावा याचिका दायर करने की तारीख ही उचित तिथि जिस पर विनिमय की दर से विदेशी मुद्रा राशि को देश की मुद्रा *(*आईएनआर*)* में परिवर्तित किया जाना है - मृतक डी आयु *45* वर्ष, *14* का गुणक लागू मृत्यु के समय, चार आश्रित होने पर, कुल आय का *1/4* हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाएगा - इस प्रकार दावेदारों को देय मुआवजे की राशि *54,49,500/-*,रु. होगी। इसके अलावा *2,00,000/-* दो बच्चों के प्यार और स्नेह के नुकसान के रूप में और *1,00,000/-* पत्नी के संघ के नुकसान के रूप में, *12%* ब्याज के साथ।

धारा *166* घातक दुर्घटना - मुआवजा - न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय की औचित्य, अंशदायी लापरवाही को क्रमशः *75:25* और *50:50* पर विभाजित करना और तदनुसार मुआवजा देना। निर्धारित चश्मदीद गवाह के साक्ष्य, एफआईआर और दुर्घटना वाहन के चालक के खिलाफ आरोप पत्र स्थापित किया कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उसकी मृत्यु हुई - इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि दुर्घटना मृतक की ओर से की गई लापरवाही के कारण हुई।

अपीलार्थी के पिता सं. 1, कार चलाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही एक बस ने उसकी कार को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वे अमेरिका में 2500 अमेरिकी डॉलर के मासिक वेतन पर कार्यरत थे। मृतक की पत्नी, उसके दो नाबालिग बच्चे और उसकी मां अप्रैल 1990 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर याचिका में दावेदार के रूप में शामिल हुए, जिसमें कुल 57,25,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया गया। दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान मृतक की मां की मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे का आकलन 18,38,500/- रुपये किया, दुर्घटना के लिए दायित्व को बस के चालक और मृतक के बीच 75:25 के अनुपात में विभाजित किया और अंशदायी

लापरवाही के लिए 25% की कटौती करते हुए 13,80,625/-. रुपये की राशि दी। उच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे का आकलन 47,09,500/- रुपये किया, लेकिन अंशदायी लापरवाही को 50:50 की दर से विभाजित किया और तदनुसार 23,45,750/- रुपये का मुआवजा दिया।

दावेदारों और बीमा कंपनी द्वारा दायर त्वरित अपील में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थे: (i) "क्या विदेशी मुद्रा ई राशि को विनिमय दर के आधार पर देश की मुद्रा में परिवर्तित किस तारीख से किया जाना है दावा याचिका दायर करने की तारीख (अप्रैल, 1990) या निर्धारण की तारीख (मई, 1993)"; (ii) क्या मृतक की ओर से कोई अंशदायी लापरवाही थी; और (iii) क्या दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित था।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिधारित किया गया:

1. मौजूदा मामले में, दावेदारों ने अप्रैल 1990 में याचिका दायर की और भारतीय रुपये में मुआवजे का दावा किया। इस तरह के मुआवज़े का दावा अमेरिकी डॉलर में नहीं किया गया था। इसलिए, फोरासोल मामले में तथ्यों और इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, दावा याचिका दायर करने की तारीख (अप्रैल, 1990) विनिमय दर तय करने के लिए उचित तारीख है जिस पर विदेशी मुद्रा राशि को देश की मुद्रा (INR) में परिवर्तित किया गया। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने विनिमय की दर

17.30 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर (जैसा कि अप्रैल, 1990 में प्रचलित थी) तय की है। [पैरा 16] [288-ई-जी]

फोरासोल बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1984 एससीआर 526-1984 (सप्ल.) एससीसी 263; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 1993 (3) सप्ल। एससीआर 22 = 1994 सप्ल (1) एससीसी 644 - पर निर्भर।

2.1 अंशदायी लापरवाही के संबंध में, मृतक की ओर से किसी भी लापरवाही का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। बस के मालिक और उसके चालक, जो ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के समक्ष पहले और तीसरे प्रतिवादी थे, ने इस आरोप से इनकार नहीं किया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। मृतक के साथ आए एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह पीडब्लू-3 की गवाही, एफआईआर के तहत दर्ज की गई। 279, 337 और 304 ए आईपीसी और बस चालक के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र। 279, 337 और ई 304 ए आईपीसी विशेष रूप से दर्शाती है कि बस चालक की मौत तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि दुर्घटना मृतक की ओर से लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि उक्त निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं था बल्कि केवल अनुमान और अनुमान पर आधारित था। [पैरा 20-23

और 26] [289-डी-एफ, जी-एच; 290-ए-सी; 291-बी] एफ

2.2 न्यायाधिकरण हाई कोर्ट दोनों ने स्वीकार किया है कि मृतक जीयू.एस.ए. में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। और उन्हें 2500 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन मिल रहा था। हाईकोर्ट ने माना कि सेवा शर्तों के अनुसार मृतक 65 वर्ष की आयु तक नौकरी में बना रह सकता था। रुपये की वार्षिक आय और विनिमय दर के आधार पर। अप्रैल, 1990 में लागू 17.30 प्रति अमेरिकी एच डॉलर, की वार्षिक आय यदि भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाए तो मृत्यु के समय 5,19,000/- रु. रुपये होगी। मृतक की आयु 45 वर्ष थी, अतः 14 का गुणक लगाने पर राशि 5,19,000 x 14 = 72,66,000/- रूपये होगी। मृतक के परिवार में 5 व्यक्ति थे अर्थात् मृतक स्वयं, पत्नी, दो बच्चे और उसकी माँ। सरला वर्मा मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार मृत्यु के समय चार आश्रित होने पर, कुल आय का 1/4 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए काटा जाएगा, और, इस प्रकार, दावेदारों को देय मुआवजा 54,49,500/- रुपये होगी. इसके अलावा, दावेदार दोनों बच्चों के प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये यानी 2,00,000/- रुपये और कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि पाने के हकदार हैं। पत्नी जो उचित प्रतीत होती है। इसलिए, कुल राशि 57,49,500/- रुपये होती है। दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 12% की

दर से ब्याज के हकदार हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय और न्यायाधिकरण के फैसले को तदनुसार संशोधित किया जाता है। [पैरा 27, 29-31] [291-सी-डी, एफ-एच; 292-ए-ई, एफ]

सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य। 2009 (5) एससीआर 1098 = 2009 (6) एससीसी 121 - का अनुसरण किया गया।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भ:

1984 एससीआर 526 पैरा 14

1993 (3) पूरक। एससीआर पैरा 22

2009 (5) एससीआर 1098 पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 2013 का 4945-4946।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के एम.एफ.ए. 2001 की संख्या 1298 और 1162 (डी) में दिनांक 12.04.2007 के निर्णय और आदेश से।

साथ ही

सीए 2013 की संख्या 4947 और 4948।

सी.एन. अपीलकर्ताओं के लिए श्री कुमार, प्रकाश रंजन नायक,

रेशमिता आर चंद्रॉ।

उत्तरदाताओं के लिए मंजीत चावल, ए.रघुनाथ।

न्यायालय का फैसला सुधांशु ज्योति मकोपदयाय द्वारा सुनाया गया।

विलंब को माफ किया तथा आवेदन स्वीकार किया गया.

2. ये अपीलें एमएफए नंबर 1162 और 1298 ऑफ 2001 (घ) में केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 12 अप्रैल, 2007 के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कोट्टायम (इसके बाद संक्षेप में 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा दावेदारों को दिए गए मुआवजे को बढ़ाया गया और इसके लिए दुर्घटना दायित्व को 50:50 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

3. वर्तमान मामले को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

16 अप्रैल, 1990 को, केके रोड पर पंपाडी मावेल स्टोर के पास एक मोटर दुर्घटना हुई, जिसमें जॉय कुरुविला (मृतक) द्वारा संचालित कार की विपरीत दिशा से आ रही बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई। जॉय कुरुविला को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उनके चार आश्रितों, अर्थात् चिन्नम्मा जॉय (मृतक की विधवा), जीजू कुरुविला उम्र 14 वर्ष, जैसन कुरुविला उम्र 11 वर्ष (मृतक के 2 नाबालिग बच्चे) और ग्रेस कुरुविला (मृतक की मां) उम्र 85 वर्ष ने एक संयुक्त

आवेदन दायर किया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 140 और 166 , निम्नलिखित मदों के लिए 57,25,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करती है: -

(क) अंत्येष्टि व्यय रु. 25,000/-

(ख) दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा रु. 1,00,000/-

(ग) मृत्यु के कारण मृतक की मृत्यु और परिणामी याचिकाकर्ताओं को आय का हानि रु. 54,00,000/-

(घ) प्रथम याचिकाकर्ता को कंसोर्टियमके नुकसान के लिए रु. 1,00,000/-

(ड.) पिता के प्रेम, स्नेह की हानि 1,00,000/-

याचिकाकर्ताओं को रु.57,25,000/-

4. दुर्घटना के समय, जॉय कुरुविला की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वह नौ साल से अधिक समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रीमैन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क शाखा में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और 2500 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे। अमेरिकी डॉलर 43,100/- रुपये के बराबर। उसे नियोक्ता द्वारा क्वार्टर उपलब्ध कराया गया था और वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। जॉय कुरुविला अपने निजी खर्चों को पूरा करने के बाद घर के खर्च और बचत के लिए अपनी

पत्नी को 30,000 रुपये प्रति माह देते थे। वे स्वस्थ थे, ऊर्जावान थे, अन्यथा दीर्घायु थे और सेवा शर्तों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक अर्थात अगले 20 वर्षों तक सेवा में बने रह सकते थे।

5. पहला दावेदार पत्नी है, दूसरा और तीसरा दावेदार बच्चे हैं और चौथा दावेदार मृतक की मां थी। पीसी कुरियन, जो तीसरा प्रतिवादी था, दुर्घटना के समय बस चला रहा था और पहला प्रतिवादी, कुंजुजम्मा मोहन बस का मालिक था। यह आरोप लगाया गया था कि दुर्घटना पूरी तरह से बस चालक, पीसी कुरियन की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और वाहन का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास वैध बीमा था। ऐसे तथ्यों के आधार पर, दावेदारों ने 18% ब्याज और लागत के साथ मुआवजे के रूप में 57,25,000/-रुपये की राशि का दावा किया।

6. नोटिस के बावजूद, बस मालिक, कुंजुजम्मा मोहन और ड्राइवर, पीसी कुरियन न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और आरोपों से इनकार नहीं किया।

7. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बाद में इसे "बीमा कंपनी" कहा जाएगा) ने अपने लिखित बयान में कुंजुजम्मा मोहन के नाम पर बस संख्या केआरके-3057 की वैध पॉलिसी के अस्तित्व को स्वीकार किया लेकिन दुर्घटना के लिए बस चालक पीसी कुरियन की ओर से तेज गति

और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप से इनकार किया है। मृतक की उम्र, व्यवसाय, मासिक आय और मुआवजे का दावा भी विवादित था। बीमा कंपनी के अनुसार, दुर्घटना मृतक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

8. पीडब्ल्यू 1 से 3 और एक्स्ट.1 से 8 और एक्स्ट. बी 1 से बी 3 की गवाही वाले साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया गया।

9. न्यायाधिकरण के समक्ष दावे के लंबित रहने के दौरान, चौथे दावेदार, मृतक की मां ग्रेस कुरुविला की मृत्यु हो गई; शेष दावेदार मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी बने रहे। दूसरे और तीसरे दावेदार, मृतक के बच्चे, जो दावा मामला दायर करने के समय नाबालिग थे, मामले की लंबित अवधि के दौरान वयस्क हो गए और उन्हें बालिग घोषित कर दिया गया।

10. न्यायाधिकरण ने पक्षों को सुनने और साक्ष्य दर्ज करने के बाद माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही और मृतक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना के दायित्व को बस के चालक और मृतक के बीच 75:25 के अनुपात में विभाजित किया। इसमें मुआवजे का आकलन रु. 18,38,500/- और मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही के

लिए 25% की कटौती के बाद, दावेदारों के पक्ष में भुगतान के लिए 12% ब्याज के साथ 13,80,625/- रुपये की राशि प्रदान की गई।

11. उच्च न्यायालय ने बस चालक और मृतक दोनों की ओर से तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के संबंध में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि की, लेकिन मुआवजे के भुगतान के लिए अंशदायी लापरवाही को 50:50 की दर से विभाजित किया। उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से 10000/-रु. मृतक द्वारा परिवार को मासिक योगदान के रूप में और यह देखा गया कि भले ही मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की गई हो, निर्भरता लाभ के रूप में 1600 अमेरिकी डॉलर से अधिक लिया जा सकता है। हालाँकि, मुआवजे का निर्धारण करते समय, उच्च न्यायालय ने निर्भरता लाभ के रूप में 1500 अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा लिया। दावा याचिका दाखिल करने की तारीख यानी अप्रैल, 1990 को प्रचलित विनिमय दर को एक्सटेंशन-ए 7 के आधार पर ध्यान में रखा गया और परिवार के लिए योगदान की गणना 25,950/- प्रति माह रुपये की गई। । इस तरह के योगदान के आधार पर, उच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे का आकलन 47,09,500/-रुपये किया। और राशि का 50% यानी दावेदारों के पक्ष में ब्याज सहित 23,45,750/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

12. दावेदारों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तों पर उच्च न्यायालय

द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती दी है: -

(i) मुआवजे की गणना के लिए विदेशी विनिमय दर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि पुरस्कार के समय यानी मई, 1993 में प्रचलित था और एक्सटेंशन-ए 8 में दिखाया गया था।

(ii) मृतक की ओर से लापरवाही से संबंधित किसी भी सबूत के अभाव में और रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के मद्देनजर, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने यह मानने में गलती की कि मृतक की ओर से लापरवाही हुई थी।

13. इस मामले में, विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:

(i) क्या विदेशी मुद्रा राशि को दावा याचिका दाखिल करने की तिथि (अप्रैल, 1990) या निर्धारण की तिथि (मई, 1993) के अनुसार विनिमय दर के आधार पर देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाना है;

(ii) क्या मृतक, जॉय कुरुविला की ओर से कोई अंशदायी लापरवाही थी

(iii) क्या दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है।

14. यह प्रश्न कि क्या किसी दावेदार/वादी को देय राशि के निर्धारण के लिए विनिमय दर तय करने की उचित तारीख, जिस पर विदेशी मुद्रा राशि को देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाना है, फोरासोल बनाम तेल

और प्राकृतिक गैस आयोग 1984 (सप्ल.) एससीसी 263 जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

"24. विदेशी मुद्रा में देय राशि की वसूली की कार्रवाई में, विनिमय की दर तय करने के लिए उचित तिथि के रूप में न्यायालय द्वारा चयन के लिए पांच तारीखें प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिस पर विदेशी मुद्रा राशि को उस देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाना है जिसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है और निर्णय लिया गया है। ये तारीखें हैं:

(1) वह तारीख जब राशि देय और देय हो गई;

(2) कार्रवाई शुरू होने की तारीख;

(3) डिक्री की तारीख;

(4) वह तारीख जब न्यायालय निष्पादन जारी करने का आदेश देता है; और

(5) वह तारीख जब डिक्रीटल राशि का भुगतान या वसूली की जाती है।

25. ऐसे मामले में जहां विदेशी मुद्रा में दिए गए अवार्ड के संदर्भ में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है, छठी तारीख भी प्रवेश करती है, प्रतियोगिता, अर्थात् अवार्ड की तारीख। हमारे सामने जो मामला है वह ऐसा है जिसमें न्यायालय द्वारा इस तरह के अवार्ड के संदर्भ में एक डिक्री

पारित की गई है।" उक्त मामले में किए गए दावे को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"70. यह सुविधाजनक होगा यदि हम अब वह प्रथा निर्धारित करें, जो हमारे अनुसार, उन मुकदमों में अपनाई जानी चाहिए जिसमें विदेशी मुद्रा में व्यक्त धनराशि पर वादी द्वारा वैध रूप से दावा किया जा सकता है और अदालत द्वारा डिक्री की जा सकती है। हमारे लिए उन मामलों को वर्गीकृत करना अनावश्यक है जिनमें ऐसा दावा किया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। ऊपर हमारे द्वारा संदर्भित अंग्रेजी निर्णयों में उन्हें पर्याप्त रूप से इंगित किया गया है। हालाँकि, ऐसे उदाहरण कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि कानून स्थिर नहीं रह सकता है, बल्कि इसे लगातार विकसित और प्रगति करना चाहिए क्योंकि जिस समाज पर यह लागू होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है और पुरानी विचारधाराओं और अवधारणाओं को त्याग दिया जाता है और नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि जिस मामले से हम चिंतित हैं वह इसी श्रेणी में आता था। ऐसे मुकदमे में, वादी, जिसे विदेशी मुद्रा में देय राशि नहीं मिली है, और इसलिए, उस राशि की वसूली के लिए अदालत की सहायता लेना चाहता है, उसके लिए दो रास्ते खुले हैं। वह या तो भारतीय मुद्रा में या उस विदेशी मुद्रा में देय राशि का दावा कर सकता है जिसमें यह देय था। यदि वह पहला विकल्प चुनता है, तो वह केवल उस

राशि के लिए मुकदमा कर सकता है जो भारतीय रुपये में परिवर्तित हो और मुकदमे में उसकी प्रार्थना केवल भारतीय मुद्रा में राशि के लिए हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, वादी को उसके कारण विदेशी मुद्रा राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करना होगा। वह या तो उस तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर ऐसा कर सकता है जब राशि देय हो गई थी क्योंकि वह उस तारीख पर राशि प्राप्त करने का हकदार था या, अपने विकल्प पर, दाखिल करने की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर कर सकता है। मुकदमा इसलिए क्योंकि यही वह तारीख है जब वह अपनी देय राशि की वसूली के लिए अदालत से सहायता मांग रहा है। किसी भी स्थिति में, अदालत की फीस और अदालत के क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमा के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्यांकन मुकदमे में दावा की गई भारतीय मुद्रा में राशि होगी। हालाँकि, वादी अपने लिए खुला दूसरा रास्ता चुन सकता है और विदेशी मुद्रा में अपनी देय राशि का दावा कर सकता है। ऐसे मुकदमे में, वादी के लिए अपने वादपत्र में उचित प्रार्थना यह होगी कि प्रतिवादी उसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों की अनुमति के अधीन वादपत्र में दावा की गई विदेशी मुद्रा राशि का भुगतान करे।, 1973, दी जा रही है और यदि विदेशी मुद्रा प्राधिकारी अपेक्षित अनुमति नहीं दे रहे हैं या प्रतिवादी विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं करना चाहता है, भले ही ऐसी अनुमति दी गई हो या

प्रतिवादी विदेशी मुद्रा में या भारतीय में भुगतान नहीं कर रहा हो। रुपये, चाहे ऐसी अनुमति दी गई हो या नहीं, प्रतिवादी वादी को फैसले की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दावा की गई विदेशी मुद्रा राशि के बराबर रुपये का भुगतान करता है। हालाँकि, अदालत की फीस और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, वादी को मुकदमे में अपने दावे का मूल्य उसके द्वारा दावा की गई विदेशी मुद्रा राशि को मुकदमा दायर करने की तारीख या तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित करके करना चाहिए। ऐसी तारीख के निकटतम या लगभग पूर्ववर्ती, अपने वादपत्र में यह बताते हुए कि विनिमय की ऐसी दर क्या है। उसे वादपत्र में यह वचन भी देना चाहिए कि वह अदालती फीस में कमी की भरपाई करेगा, यदि कोई हो, यदि फैसले की तारीख पर, उस समय प्रचलित विनिमय दर पर, विदेशी मुद्रा राशि के बराबर रुपया होगा। न्यायालय-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए वादपत्र में उल्लिखित से अधिक है। ऐसे मुकदमे की सुनवाई में, डिक्री पारित करने से पहले, अदालत को वादी को फैसले की तारीख पर या फैसले की तारीख से निकटतम या सबसे पूर्ववर्ती तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को साबित करने के लिए कहना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय देने के बाद, अदालत शेष निर्णय और डिक्री के पारित होने पर रोक लगा सकती है और वादी को विनिमय की ऐसी दर साबित करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को

स्थगित कर सकती है। अदालत द्वारा पारित किया जाने वाला डिक्री ऐसा होना चाहिए जो प्रतिवादी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों की अपेक्षित अनुमति के अधीन वादी को अदालत द्वारा तय की गई विदेशी मुद्रा राशि का भुगतान करने का आदेश दे। , 1973, दी जा रही है, और ऐसी स्थिति में जब विदेशी मुद्रा प्राधिकारी अपेक्षित अनुमति नहीं दे रहे हैं या प्रतिवादी विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं करना चाहता है, भले ही ऐसी अनुमति दी गई हो या प्रतिवादी विदेशी मुद्रा में या भारतीय में भुगतान नहीं कर रहा हो। रुपये, चाहे ऐसी अनुमति दी गई हो या नहीं, ऐसी विदेशी मुद्रा राशि के बराबर, जिसे पूर्वोक्त रूप से अदालत के समक्ष साबित की गई विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। डिक्री को अपील या अन्य कार्यवाहियों में चुनौती दिए जाने की स्थिति में और ऐसी अपील या अन्य कार्यवाहियों का निर्णय पूर्णतः या आंशिक रूप से वादी के पक्ष में होने की स्थिति में, अपीलीय अदालत या डिक्री को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहियों में आवेदन की सुनवाई करने वाली अदालत को इसका पालन करना चाहिए। अपीलीय डिक्री की तारीख या ऐसे आवेदन पर उसके आदेश की तारीख पर या ऐसे डिक्री या आदेश की तारीख से निकटतम या सबसे पूर्ववर्ती तारीख पर प्रचलित विनिमय दर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट के समान प्रक्रिया। यदि ऐसी विनिमय दर उस डिक्री की दर से भिन्न है जिसे चुनौती

दी गई है, तो अदालत को अपने अपीलीय डिक्री या अंतिम आदेश द्वारा विनिमय दर के संबंध में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, निष्पादन केवल डिक्री, अपीलीय डिक्री या अंतिम आदेश, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट रुपये के बराबर राशि के लिए जारी किया जा सकता है। निःसंदेह, ये प्रश्न तब नहीं उठेंगे जब प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई अपील या अन्य कार्यवाही के लंबित रहने पर डिक्री निष्पादित हो गई हो या उसके तहत वादी को धन प्राप्त हो गया हो।"

15. रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में । 1994 सप्ल (1) एससीसी 644, इसी तरह का प्रश्न विचार के लिए आया था। उक्त मामले में, एक विदेशी पुरस्कार विचाराधीन था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ब्याज सहित अमेरिकी डॉलर में इसका फैसला सुनाया। उक्त मामले में फोरासोल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था:

143. फोरासोल मामले में निर्णय के अनुसार उक्त राशि को इस निर्णय के समय प्रचलित रुपया-डॉलर विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 1993 को रुपया-डॉलर विनिमय (बिक्री) दर 31.53 रुपये प्रति डॉलर थी।

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

146. परिणामस्वरूप, 1990 के सीए नंबर 71 और 71-ए और 1992 के सीए नंबर 379 को खारिज कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को इस निर्देश के साथ पुष्टि की जाती है कि पुरस्कार के संदर्भ में 12,333,355.14 अमेरिकी डॉलर की राशि होगी। रेनुसागर द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को देय है, जिसमें से 6,289,800.00 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान रेनुसागर द्वारा डिक्रीटल राशि के निर्वहन में पहले ही किया जा चुका है और डिक्री के तहत रेनुसागर द्वारा देय शेष राशि 6,043,555.14 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपये में रूपांतरण पर है। इस निर्णय के समय प्रचलित रुपया-डॉलर विनिमय दर 31.53 रुपये प्रति डॉलर है जो 19,05,53,293.56 रुपये है। रेनूसागर इस फैसले की तारीख से भुगतान तक 19,05,53,293.56 रुपये की इस राशि पर 18 प्रतिशत की दर से भविष्य में ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

16. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि दावेदारों ने अप्रैल, 1990 में एक याचिका दायर की (24 मार्च, 1990 को शपथ पत्र पर शपथ ली) और INR यानी 57,25,000/- रुपये में मुआवजे का दावा किया। इस तरह के मुआवज़े का दावा अमेरिकी डॉलर में नहीं किया गया था। उक्त कारण से और फोरासोल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, जैसा कि

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में किया गया है, हम मानते हैं कि दावा याचिका दाखिल करने की तारीख (अप्रैल, 1990) उचित है विनिमय दर तय करने की तारीख जिस पर विदेशी मुद्रा राशि को देश की मुद्रा (आईएनआर) में परिवर्तित किया जाना है। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने विनिमय दर 17.30 रुपये (जैसा कि अप्रैल, 1990 में प्रचलित था) तय करने के लिए एक्सटेंशन-ए 7 पर सही भरोसा किया है।

17. दूसरा प्रश्न मृतक की अंशदायी लापरवाही से संबंधित है। दावेदारों के अनुसार, दुर्घटना बस चालक, पीसी कुरियन की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और मृतक जॉय कुरुविला की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।

इसके विपरीत, बीमा कंपनी के अनुसार, दुर्घटना मृतक की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई, जो नशे की हालत में था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सटेंशन-ए 5 पर भरोसा किया।

18. तीन गवाह, पीडब्लू.1 से पीडब्लू.3 तक, न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुए। पार्टियों ने दस्तावेजी साक्ष्य, एक्सटेंशन ए-1 से एक्सटेंशन ए-8, एक्सटेंशन रखे। बी1 और बी2. दावेदारों की ओर से, उन्होंने बस चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने को दिखाने के लिए मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया। बीमा कंपनी की ओर से वकील ने

मृतक की ओर से लापरवाही का सुझाव देने के लिए एक्सटेंशन-बी2 'सीन महाजार' और एक्सटेंशन-ए 5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा किया।

19. उच्च न्यायालय ने एक्सटेंशन-बी2 'सीन महाजार' और एक्सटेंशन-ए 5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माना कि मृतक की ओर से भी लापरवाही हुई थी।

20. पक्षों को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

वाहन के मालिक कुंजुजम्मा मोहन और बस के चालक, पीसी कुरियन, जो न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष पहले और तीसरे प्रतिवादी थे, ने इस आरोप से इनकार नहीं किया था कि दुर्घटना बस का संचालक लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी।

21. पीडब्लू-3, एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यात्रा के दौरान मृतक के साथ था। उन्होंने कहा कि विपरीत दिशा से आ रही बस ने मृतक द्वारा चलायी जा रही कार को टक्कर मार दी और यह दुर्घटना बस चालक की तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

22. एक्सटेंशन-ए 1, पंपडी पुलिस द्वारा बस चालक पीसी कुरियन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 , 337 और 304 ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर से पता चलता है कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से

गाड़ी चलाने के कारण हुई। जांच के बाद, पुलिस ने बस चालक के खिलाफ धारा 279 , 337 और 304 ए आईपीसी के तहत आरोप पत्र (एक्सटेंशन-ए 4) प्रस्तुत किया, जिसमें विशिष्ट आरोप लगाया गया कि बस चालक ने बस की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण जॉय कुरुविला की मौत कारित की। 16 अप्रैल, 1990 को शाम 4.50 बजे प्रत्यक्ष साक्ष्य के मद्देनजर, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने माना कि दुर्घटना बस चालक की ओर से तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

23. मृतक की ओर से किसी लापरवाही का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। एक्सटेंशन-बी2, 'सीन महाज़ार' भी मृतक की ओर से किसी भी लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने का सुझाव नहीं देता है।

24. दुर्घटना के बाद वाहनों की मात्र स्थिति, जैसा कि दृश्य महाज़ार में दिखाया गया है, किसी एक या दूसरे की ओर से तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का पर्याप्त सबूत नहीं दे सकती है। जब विपरीत दिशाओं से आ रहे दो वाहन टकराते हैं, तो वाहनों की स्थिति और उसकी दिशा आदि कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे वाहनों की गति, टक्कर की तीव्रता, टक्कर का कारण, वह स्थान जहां एक वाहन ने दूसरे को टक्कर मारी, आदि। दुर्घटना स्थल के बारे में कोई भी सुझाव दे सकता है

या अनुमान लगा सकता है कि दुर्घटना किस प्रकार हुई, लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष या पुष्ट साक्ष्य के अभाव में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या चालक की ओर से लापरवाही हुई थी। ऐसे प्रत्यक्ष या पुष्ट साक्ष्य के अभाव में, न्यायालय किसी व्यक्ति की ओर से लापरवाही के बारे में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं दे सकता है।

25. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सटेंशन-ए 5 मृत्यु के समय मृतक की स्थिति को दर्शाता है। उक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि मृतक ने पहले ही भोजन कर लिया था क्योंकि उसका पेट आधा भरा हुआ था और उसमें स्प्रिट की तेज गंध वाले तरल पदार्थ में चावल, सब्जियां और मांस के टुकड़े थे।

26. उपरोक्त साक्ष्य, एक्सटेंशन-ए 5 स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि मृतक ने शराब पी थी, लेकिन उसके आधार पर, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि दुर्घटना के समय मृतक तेजी से और लापरवाही से कार चला रहा था। एक्सटेंशन-बी2, 'सीन महाजार' और एक्सटेंशन-ए 5, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित मात्र संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता, खासकर, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे पीडब्लू.3, स्वतंत्र चश्मदीद,एक्सटेंशन।-ए 1(एफआईआर),एक्सटेंशन-ए 4(चार्जशीट)और एक्सटेंशन-बी1(एफआई स्टेटमेंट) रिकॉर्ड में हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि न्यायाधिकरण और उच्च

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि उक्त दुर्घटना मृतक की ओर से लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि उक्त निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं था, बल्कि केवल अनुमान पर आधारित था। ।

27. अंतिम प्रश्न न्यायसंगत एवं उचित मुआवज़े से संबंधित है। न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट दोनों ने माना है कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 45 वर्ष थी; वह फ्रीमैन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क शाखा, यूएसए में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें 2500 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन मिल रहा था। उच्च न्यायालय ने माना कि सेवा शर्तों के अनुसार मृतक 65 वर्ष की आयु तक नौकरी जारी रख सकता था।

28. एक्सटेंशन-ए 6, मृतक के नियोक्ता यानी फ्रीमैन मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, यूएसए द्वारा 23 अप्रैल, 1990 को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है जो दर्शाता है कि उनका वार्षिक वेतन 30,000 अमेरिकी डॉलर था। वह 9 वर्षों तक उनके रोजगार में था और उसकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी और उसका रोजगार स्थायी प्रकृति का था। मृतक 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बना रहेगा। राजनयिक और कांसुलर अधिकारी (शपथ और शुल्क) अधिनियम , 1948 की धारा 3 के अनुसार, एक्सटेंशन-ए 6 को नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया था और भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था।

29. उपरोक्त वार्षिक आय और रुपये की विनिमय दर के आधार पर। अप्रैल, 1990 में लागू 17.30 प्रति अमेरिकी डॉलर (एक्सटेंशन-ए 7), यदि भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाए तो मृत्यु के समय मृतक की वार्षिक आय 30,000 x 17.30 = 5,19,000/- होगी। इसलिए, सरला वर्मा एवं अन्य के निर्णय के अनुसार, मृतक की आयु 45 वर्ष थी । वी. दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य , (2009) 6 एससीसी 121, 14 का गुणक लागू होगा। लेकिन हाई कोर्ट और न्यायाधिकरण ने यह गलत ठहराया कि 15 का गुणक लागू होगा। इस प्रकार 14 का गुणक लगाने पर मुआवजे की राशि 5,19,000 x 14 = 72,66,000/- रुपये होगी। मृतक के परिवार में 5 व्यक्ति थे अर्थात मृतक स्वयं, पत्नी, दो बच्चे और उसकी माँ। सरला वर्मा (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार मृत्यु के समय चार आश्रित होने पर, कुल आय का 1/4 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए काटा जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि मृतक 2,500 अमेरिकी डॉलर में से 500 अमेरिकी डॉलर यानी अपनी आय का 1/5 हिस्सा खर्च करता था। इसलिए, यदि कुल आय का 1/4 भाग अर्थात रु. मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के लिए 18,16,500/- रुपये की कटौती की जाएगी, परिवार के लिए योगदान (72,66,000 रुपये - 18,16,500/- =) रुपये 54,49,500/- होगा। उपरोक्त मुआवजे के अलावा, दावेदार दोनों बच्चों के प्यार और स्नेह के लिए 1,00,000/- रुपये यानी

2,00,000/- रुपये और कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये पत्नी को देना उचित प्रतीत होता है। इसलिए, कुल राशि 57,49,500/- रुपये होती है।

30. दावेदार मुआवजे की उक्त राशि को याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 12% ब्याज के साथ प्राप्त करने के हकदार हैं, अवार्ड में उल्लिखित बाकी शर्तों को बरकरार रखते हुए।

31. तदनुसार, हम दावेदारों द्वारा दायर की गई अपीलों को अनुमति देते हैं और आंशिक रूप से बीमा कंपनी द्वारा की गई अपीलों को अनुमति देते हैं, जहां तक यह गुणक के आवेदन से संबंधित है। 2001 के एमएफए संख्या 1162 और 1298 में केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 12 अप्रैल, 2007 का निर्णय और न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। जो राशि दावेदारों को पहले ही भुगतान की जा चुकी है, उसे समायोजित किया जाएगा और शेष राशि ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार ब्याज सहित तीन महीने के भीतर भुगतान की जाएगी। लागत के संबंध में कोई अलग आदेश नहीं होगा।

.....न्यायाधिपति

[जी.एस.सिंघवी]

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से लव प्रजापति अनुवादक (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।